पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.11512

=====

प्रभात कुमार पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के निवासी मोहल्ला-बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी,
भूतनाथ रोड, पटना-800026

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. अध्यक्ष के माध्यम से भारत संघ रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली 110001
2. सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली 110001।
3. संयुक्त सचिव (ई)-II, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली 110001।
4. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, पो.-दिग्धी कलान, थाना-हाजीपुर, जिला-हाजीपुर में वैशाली, 844101।
5. महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, पी. ओ.-दिग्गी कलां, थाना-हाजीपुर, जिला-वैशाली, 844101।
6. एपीओ/गज, महाप्रबंधक (ओ) का कार्यालय, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर 844101।
7. महाप्रबंधक, मध्य रेलवे, मुंबई।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

- =====
- अ. पदोन्नति-प्रतिनियुक्ति-प्रतिनियुक्ति के कारण विभागीय परीक्षा में अनुपस्थिति-उस तिथि से दी जाने वाली काल्पनिक पदोन्नति जो उसके समान/कनिष्ठ पदों के व्यक्तियों को दी गई है।

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.11512

=====

प्रभात कुमार पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के निवासी मोहल्ला-बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी,
भूतनाथ रोड, पटना-800026

.....याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. अध्यक्ष के माध्यम से भारत संघ रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली
110001
2. सचिव, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली 110001।
3. संयुक्त सचिव (ई)-II, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली 110001।
4. महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, पो.-दिग्धी कलान, थाना-हाजीपुर, जिला-
हाजीपुर में वैशाली, 844101।
5. महाप्रबंधक (कार्मिक), पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, पी. ओ.-दिग्गी कलां, थाना-हाजीपुर,
जिला-वैशाली, 844101।
6. एपीओ/गज, महाप्रबंधक (ओ) का कार्यालय, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर 844101।
7. महाप्रबंधक, मध्य रेलवे, मुंबई।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री जयंत कुमार कर्ण, अधिवक्ता

श्री हेमंत कुमार कर्ण, अधिवक्ता

श्री जय कर्ण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए : श्री नरेश दीक्षित, वरिष्ठ सी. जी. सी.

श्री श्याम बिहारी सिंह, सी. जी. सी.

सुश्री कल्पना, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय श्री न्यायमूर्ति पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तिथि:- 25.01.2024

याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण पटना पी. के सं. 2020 के ओ.ए. सं.339 में दिनांकित 15.10.2020 को पारित आदेश, अनुलग्नक पी-13 के माध्यम से, 2020 का समीक्षा आवेदन सं.09 में पारित दिनांकित 07.12.2020 के आदेश के साथ पठित 2020 का विविध आवेदन सं. 208 में पारित दिनांकित 7.12.2020 के आदेश,

अनुलग्नक पी-10 के माध्यम से महाप्रबंधक ई सी आर द्वारा निर्गत दिनांकित 21.08.2020 के आदेश एवं अनुलग्नक पी-15 के दिनांकित 17.12.2020 का आदेश का अभ्याक्रमण किया एवं इसके अलावा वरिष्ठ शाखा अभियंता (विद्युत) के पद से ग्रुप बी - सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति हेतु उसके नाम पर विचारण वास्ते एक निर्देश की मांग की।

2. याचिकाकर्ता मुंबई रेलवे डिवीजन में काम करते हुए, वह वर्ष 1997 में पूर्वी मध्य रेलवे में प्रतिनियुक्ति पर थे और 2005 तक प्रतिनियुक्ति पर बने रहे, इसके बाद उनकी सेवाओं को ईसीआर हाजीपुर में अवशोषित कर लिया गया। इस पृष्ठभूमि में ऐसे व्यक्ति जो समान रूप से स्थित थे और जो मुंबई रेलवे मंडल में काम कर रहे थे, उनके नामों पर समूह बी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया और याचिकाकर्ता के नाम की अनदेखी की गई। निस्संदेह, याचिकाकर्ता को कुछ विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी जो वर्ष 2001 में आयोजित की गई थी। इस तरह की विभागीय परीक्षा वर्ष 2001 में मुंबई रेलवे मंडल द्वारा आयोजित की गई थी और इसे याचिकाकर्ता को अधिसूचित नहीं किया गया है जो प्रतिनियुक्ति पर था। दूसरी ओर, मुंबई रेलवे डिवीजन-उत्तरदाता 7 ने पैरा 14 पर इस हद तक दावा किया है कि समूह-बी सहायक अभियंता के पद के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने के संबंध में याचिकाकर्ता को सूचित करने के लिए ऋण लेने वाले प्राधिकारी-ईसीआर हाजीपुर को एक संचार था, इसी का विरोध ईसीआर हाजीपुर उत्तरदाताओं द्वारा पैरा 7 पर अपने जवाबी हलफनामे में किया गया है, जिसमें मुंबई रेलवे डिवीजन से संचार की ऐसी प्राप्ति से इनकार किया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकालना होगा कि समूह-बी सहायक अभियंता(पदोन्नत पद) के पद पर जहां तक याचिकाकर्ता के नाम का विचार का प्रश्न है, याचिकाकर्ता को मुंबई रेल प्रभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं प्रदान किया गया। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता ने संबंधित प्राधिकारी से संपर्क किया है और उन्होंने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। परिणाम में याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण के समक्ष

मूल आवेदन दायर करने के उपाय का आह्वान किया और इसे मूल आवेदन दाखिल करने में देरी के कारण प्रारंभ में ही अस्वीकार कर दिया एवं इस अदालत द्वारा रिट याचिका में इसकी पुष्टि की गई थी। इसके बाद उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता प्रतिनिधित्व दायर करने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता ने प्रतिनिधित्व समर्पित किया था और इसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता ने एक बार फिर उपरोक्त राहत के संबंध में कैट का दरवाजा खटखटाया, जिसे खारिज कर दिया गया और उसके बाद कैट द्वारा याचिकाकर्ता को विभागीय परीक्षा के कुछ संचार के रूप में कुछ त्रुटियां बताई गईं और उन्हें इस हद तक सुधार दिया गया कि विभागीय परीक्षा आयोजित करने के संबंध में याचिकाकर्ता को कोई संचार नहीं किया गया था। उन्होंने समीक्षा याचिका भी दायर की है और समीक्षा याचिका को विविध आवेदन में परिवर्तित कर दिया गया था और इसे खारिज कर दिया गया था, इसलिए वर्तमान रिट याचिका।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता मुंबई रेलवे डिवीजन से ईसीआर हाजीपुर में प्रतिनियुक्ति पर था, मुंबई रेलवे डिवीजन में काम करने वाले रेलवे के समान रूप से स्थित कर्मचारियों को जो भी लाभ उपलब्ध कराया गया था, उसे याचिकाकर्ता को तब तक बढ़ाया जाना आवश्यक था जब तक कि उसका ग्रहणाधिकार मुंबई रेलवे प्रभाग में निहित है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्ष 2001 में समूह बी-सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से विभागीय परीक्षा आयोजित की गई थी। याचिकाकर्ता को ऐसी परीक्षा में भाग लेने से मना कर दिया गया है। दूसरी ओर, ईसीआर हाजीपुर में उनके अवशोषण के बाद समान परीक्षा आयोजित की गई और उन्होंने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें पदोन्नत किया गया। इस पृष्ठभूमि में विचार करने के लिए सवाल यह है कि क्या वह मुंबई रेलवे डिवीजन में अपने

जूनियर की पदोन्नति की तारीख से पूर्वव्यापी पदोन्नति के हकदार हैं या नहीं? (काल्पनिक आधार पर)। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि अनुलग्नक-ए/8 में, वह भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली खंड 1 के पैरा 206.2 और 228 पर इस हद तक भरोसा कर रहा है कि उन प्रतिनियुक्तिवादियों में से कुछ सेवा और अन्य लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने यह अवगत तक्ष कराया है कि उपरोक्त खंडों को इस तथ्य के साथ पठन करते हुए कि मुंबई रेलवे डिवीजन द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के बारे में याचिकाकर्ता को सूचित नहीं किया गया था ताकि मुंबई रेलवे डिवीजन द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में (याचिकाकर्ता को) भाग लेने का अवसर मिल सके। न्यायाधिकरण भारतीय रेलवे प्रतिष्ठान नियमावली खंड-1 के 206.1 और 228 की जांच करने में विफल रहा है।

4. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और समर्पित किया कि याचिकाकर्ता को परीक्षा लिखने का अवसर प्रदान किया गया था जैसा कि सातवें उत्तरदाताओं के जवाबी हलफनामे के पैरा 14 से स्पष्ट है।

5. इसलिए, उत्तरदाताओं की ओर से कोई दुर्बलता नहीं है। उत्तरदाताओं ने कैट के आदेशों का इस हद तक समर्थन किया है कि आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा जारी किए गए विवादित आदेश के साथ पढ़े गए तीनों आदेशों में कोई कमजोरी नहीं है।

6. संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना।

7. वर्तमान वाद में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता मुंबई रेलवे मंडल में समूह बी-सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति का लाभ पाने का हकदार है, अथवा नहीं जब वह ईसीआर हाजीपुर में प्रतिनियुक्ति पर था। निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता वर्ष 1997 से 2005 तक मुंबई रेलवे मंडल से ईसीआर हाजीपुर में प्रतिनियुक्ति पर थे, जिस वर्ष उन्हें ईसीआर में शामिल किया गया था। मुंबई रेलवे डिवीजन में समूह-बी

सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति वर्ष 2001 में हुई थी। समूह बी सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंडों में से एक यह है कि संबंधित कर्मचारी को कुछ विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। कहा जाता है कि विभागीय परीक्षा वर्ष 2001 में मुंबई रेलवे मंडल द्वारा आयोजित की गई थी, जब याचिकाकर्ता ईसीआर हाजीपुर में प्रतिनियुक्त पर था। विभागीय परीक्षा के संचालन के बारे में याचिकाकर्ता को नहीं बताया गया था जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा समूह बी-सहायक अभियंता पदोन्नति के उद्देश्य से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना उसके नियंत्रण से बाहर था क्योंकि वह ईसीआर, हाजीपुर में प्रतिनियुक्त पर था। इसलिए, याचिकाकर्ता, जो ईसीआर, हाजीपुर में प्रतिनियुक्त पर था, के दावे की अनदेखी करके मुंबई रेलवे डिवीजन में समूह बी-सहायक अभियंता के पद के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने में मुंबई रेलवे डिवीजन की ओर से कुछ खामियां हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं होने पर, उसे विभागीय परीक्षा में भाग लेने और पदोन्नति अर्जित करने के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। यह सच है कि याचिकाकर्ता ने संबंधित समय पर समूह बी-सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और यह उसके नियंत्रण से बाहर था। दूसरी ओर, उन्होंने ईसीआर में अपने अवशोषण के संदर्भ में ईसीआर में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है। पैरा 206.1 और 228 जो नीचे लिखे अनुसार हैं:

“206.1 प्रतिनियुक्त पर कर्मचारियों पर विचार ऐसे मामलों में जहां चयन करने के लिए पात्र कर्मचारी प्रतिनियुक्त/अन्यत्र अस्थाई नियुक्त पर विदेश में हैं और कुछ महीनों के समय में उनके लौटने की संभावना नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में आयोजित चयन को उनकी वापसी की प्रतीक्षा किए बिना अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उनकी वापसी पर उन्हें उसके बाद आयोजित पहले चयन के लिए बुलाया जाना चाहिए और चयन में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें विदेश में उनकी अनुपस्थिति के दौरान बनाए गए पैनल में

अपचाराथ शामिल करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी को इस प्रकार एनेल में शामिल किया जाता है तो उसे कोई बकाया देय नहीं होगा और समूह 'बी' में भुगतान करने की पात्रता उसकी वास्तविक कार्यवाहक पदोन्नति की तारीख से ही शुरू होगी। पैनेल के लिए इस प्रकार विस्तारित बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए। देश के भीतर कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले योग्य कर्मचारियों के संबंध में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों को पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाए और चयन के समय उन पर विचार बिना चूक के किया जाना चाहिए।

228. त्रुटिपूर्ण पदोन्नति-(I) कभी-कभी प्रशासनिक त्रुटियों के कारण, कर्मचारियों को उच्च श्रेणी में पदोन्नति के लिए अनदेखी या तो योग्य कर्मचारियों की सापेक्ष वरिष्ठता के गलत आवंटन के कारण या पदोन्नति का आदेश देते समय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूर्ण तथ्य नहीं रखे जाने के कारण या कुछ अन्य कारणों से हो सकता है। मोटे तौर पर, प्रशासनिक त्रुटियों के कारण वरिष्ठता का नुकसान दो प्रकार का हो सकता है:

(i) जहां किसी व्यक्ति को प्रशासनिक त्रुटियों के कारण पदोन्नत नहीं किया गया है और

(ii) जहां किसी व्यक्ति को पदोन्नत किया गया है लेकिन प्रशासनिक त्रुटियों के कारण उस तारीख को नहीं जिससे उसे पदोन्नत किया गया होगा।

ऐसे प्रत्येक मामले से उसके गुण-दोष के आधार पर निपटा जाना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने प्रशासनिक त्रुटियों के कारण पदोन्नति खो दी है, उन्हें पदोन्नति की तारीख की परवाह किए बिना, पहले से ही पदोन्नत अपने

कनिष्ठों की तुलना में सही वरिष्ठता दी जानी चाहिए। पदोन्नति पर उच्च श्रेणी में वेतन उचित समय पर निश्चित उपचाराथ किया जा सकता है। वास्तविक पदोन्नति की तारीख से बढ़े हुए वेतन की अनुमति दी जा सकती है। इस कारण कोई बकाया देय नहीं होगा क्योंकि उन्होंने वास्तव में उच्च पदों के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ नहीं लिया था।

8. उपरोक्त प्रावधान को पढ़कर, यह स्पष्ट है कि कुछ अधिकार उन कर्मचारियों के पास निहित हैं जो प्रतिनियुक्ति पर हैं और पदोन्नति के उद्देश्य से किसी कर्मचारी के नाम की अनदेखी करते हैं। न्यायाधिकरण ने इस मामले के तथ्यात्मक पहलू की सराहना नहीं की है कि याचिकाकर्ता को विभागीय परीक्षा में भाग लेने से इनकार कर दिया गया है और आगे उपरोक्त पैरा 206.1 और 228 ने इस हद तक ठीक से व्याख्या नहीं की है कि याचिकाकर्ता के पास इन दो खंडों के तहत कुछ उपाय हैं। इस पृष्ठभूमि में अंततः विचार के लिए सवाल यह है कि क्या याचिकाकर्ता काल्पनिक आधार पर पूर्वव्यापी पदोन्नति का हकदार है या नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने 2001 से मुंबई रेलवे डिवीजन में अपने तत्काल कनिष्ठ के बराबर समूह बी-सहायक अभियंता के पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है, साथ ही विभागीय परीक्षा में बैठने और इसे उत्तीर्ण करने के मामले में यह उनके नियंत्रण से बाहर था। दूसरी ओर, उन्होंने समान परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्हें ईसीआर हाजीपुर में पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं होने पर, काल्पनिक आधार पर समूह बी-सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति से इनकार करना मनमाना होगा। न्यायाधिकरण ने इस बात की सराहना नहीं की है कि याचिकाकर्ता को परीक्षा नहीं लिखने के अवसर और मुंबई रेलवे मंडल में समूह बी - सहायक अभियंता में प्रोन्नति के लाभ से वंचित कर दिया गया है। अतः, उसे समूह बी - सहायक अभियंता के पद पर उस तिथि से जब उसके निकटतम कनिष्ठ मुंबई रेल मंडल में उपरोक्त पद पर प्रोन्नत हुए थे, उसे पदोन्नत कर मुआवजा दिया जाना है। इस पर ध्यान दिया जाएगा और

याचिकाकर्ता को उसके कनिष्ठ की तारीख से पदोन्नत किया जाएगा। समूह बी-सहायक अभियंता के पद पर इस तरह की पूर्वव्यापी पदोन्नति पर केवल काल्पनिक आधार पर विचार किया जाना चाहिए, दूसरे शब्दों में, वेतन निर्धारण और परिणामी सेवा लाभों के उद्देश्य से। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता अपने कनिष्ठ की पदोन्नति की तारीख से लेकर ईसीआर हाजीपुर द्वारा उसे दी जाने वाली नियमित पदोन्नति तक किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं है।

9. तदनुसार, अनुलग्नक-पी-13 दिनांकित 15.10.2020, अनुलग्नक-पी-10 दिनांकित 21.08.2020 और अनुलग्नक पी-15 दिनांकित 17.12.2020 को अलग रखा गया है। लिखित याचिका की अनुमति है।

10. सेवा लाभ याचिकाकर्ता को वित्तीय लाभों के अलावा वेतन के निर्धारण के रूप में दिए जाएंगे और तीन महीने की अवधि के भीतर उन पर विचार किया जाएगा। संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विस्तृत बोलने का आदेश पारित करते समय, यदि इस संबंध में कोई विवाद है कि सक्षम प्राधिकारी कौन होगा, क्योंकि याचिकाकर्ता अनियंत्रित था, क्योंकि याचिकाकर्ता की सेवाओं को ईसीआर, हाजीपुर में अवशोषित किया गया है, उन परिस्थितियों में, इसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है और उसके बाद इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में बोलने का आदेश पारित करने के उद्देश्य से पत्र प्रेषित किया जाएगा।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

सौरभकर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।